देश में सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य

गैस की कमी नहीं, सरकार ने दी बड़ी राहत

ऑनलाइन बुकिंग 94 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, 30 मार्च. देश में मौजूदा वैश्विक तनाव के बावजूद घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य बनी हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और एक दिन में 55 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए.

सरकार ने सप्लाई को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है. साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर बुकिंग न करें और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच देश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में 94 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एक दिन में 55 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए गए हैं. सरकार ने आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित कोटे के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है. साथ ही डिलीवरी में पारदर्शिता लाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारित सिस्टम का उपयोग बढ़ाकर 84 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है.

> इसके अलावा तेल कंपनियों ने भी हजारों पेट्रोल पंपों और वितरकों पर औचक निरीक्षण किए हैं. सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें. साथ ही डिजिटल माध्यमों के उपयोग और वैकल्पिक ईंधनों जैसे पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि सप्लाई पर दबाव कम किया जा सके.

रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 पार

नई दिल्ली, 30 मार्च. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 के पार पहुंच गया, जो ऐतिहासिक निचले स्तर का संकेत है. सोमवार के कारोबारी सत्र में रुपया 0.3त्न गिरकर इस रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की विदेशी मुद्रा पोजिशन पर सख्ती करने के बावजूद गिरावट पर लगाम नहीं लग पाई. विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, ऊंची कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की निकासी रुपये और भारतीय बाजार दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं. इस गिरावट के असर से निफ्टी में भी करीब 2% की कमजोरी दर्ज की गई. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 के स्तर को पार कर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गया.

अमेरिका-ईरान तनाव से सोने की चमक फीकी

गोल्ड 0 .68 प्रतिशत गिरा, निवेशकों की धारणा कमजोर

नई दिल्ली, 30 मार्च. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है. सोमवार को सोने की कीमत 0.50त्न से ज्यादा गिरकर 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब आ गई, जबकि चांदी में हल्की तेजी देखने को मिली. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश से कुछ हद तक हटता नजर आ रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने सोने की मांग पर दबाव बनाया है. वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कीमती धातुओं के बाजार में कमजोरी का रुख देखने को मिला है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की धारणा में बदलाव के संकेत मिले हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना करीब 0.68 प्रतिशत गिरकर 1,43,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं चांदी में हल्की बढ़त के बावजूद शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिला. वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले सप्ताह की तेजी लगभग खत्म हो गई है. आमतौर पर भू-राजनीतिक तनाव के समय सोना सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत होता है, लेकिन इस बार निवेशकों का रुझान कुछ कमजोर पड़ा है.

> विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई की आशंकाएं बाजार को प्रभावित कर रही हैं. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने की संभावना भी सोने की कीमतों पर दबाव डाल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में करीब 1.7 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई, जबकि कॉमेक्स में यह 4,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता नजर आया.

शेयर बाजारों में आई बड़ी गिरावट

1,636 अंक लुढ़का सेंसेक्स

488 अंक पर फिसला निफ्टी

मुंबई, 30 मार्च. विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 1,635.67 अंक (2.22 प्रतिशत) लुढ़ककर 25 महीने से अधिक के निचले स्तर 71,947.55 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 488.20 अंक यानी 2.14 प्रतिशत टूटकर 22,331.40 अंक पर बंद हुआ जो इसका करीब एक साल का निचला स्तर है. पश्चिम एशिया संकट और उद्योगों पर उनके

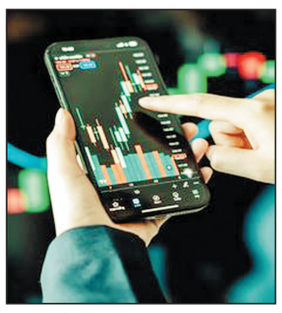

प्रभाव के कारण शेयर बाजारों में शुरू से ही बिकवाली हावी रही. सेंसेक्स एक हजार अंक से अधिक की गिरावट में खुला. दोपहर बाद बाजार पर दबाव और बढ़ गया. मझौली तथा छोटी कंपनियों में बिकवाली ज्यादा देखी गयी.

वृहत सूचकांकों में निफ्टी मिडकैप-50 में 2.68 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 2.66 फीसदी की गिरावट रही. बैंकिंग और वित्तीय शेयरों पर भारी दबाव रहा. ऑटो, मीडिया, एफएमसीजी, रियलटी, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, फार्मा और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांकों में भी अधिक गिरावट रही.

> सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर पांच प्रतिशत से ऊपर टूट गया. भारतीय स्टेट बैंक, इंडिगो, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और ट्रेंट के शेयर तीन से चार प्रतिशत तक लुढ़के. भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और सनफार्मा के शेयर दो से तीन प्रतिशत फिसल गये.

औद्योगिक उत्पादन फरवरी में 5 .2 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, 30 मार्च (वार्ता) विनिर्माण क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन से इस साल फरवरी में देश के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. इस साल जनवरी में इसमें 5.1 प्रतिशत और पिछले साल फरवरी में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी. केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) छह प्रतिशत बढ़ा. खनन क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. विनिर्माण क्षेत्र लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है. चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच इसकी वृद्धि दर पांच प्रतिशत दर्ज की गयी है.

डिजिटल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई पहचान : जियो फाइबर

भोपाल-रायपुर, 30 मार्च. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जियो ने एक बार फिर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में सबसे अधिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े हैं. जनवरी 2026 में जियो से 6.2 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े, जबकि जिओ फाइबर और जिओ एयरफाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं को 66 हजार से अधिक नए उपभोक्ताओं ने अपनाया.

टीआरएआई के आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.49 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और वायरलाइन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 31.6 लाख से ज्यादा है. इनमें जियो के 4.9 करोड़ मोबाइल ग्राहक और 19.1 लाख से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहक शामिल हैं, जो इसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाते हैं. मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को नई गति देते हुए रिलायंस जियो की जिओ फाइबर और एयर फाइबरसेवाएं तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रही हैं. इन सेवाओं के माध्यम से अब तक दोनों राज्यों में 19 लाख से अधिक घर हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार, व्यापार और घरेलू जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है.

शिक्षा, रोजगार और जीवनशैली में बदलाव- जिओ फाइबर की उपलब्धता ने छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई डिजिटल स्किल्स सीखने के अवसर बढ़ाए हैं. वहीं, कामकाजी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल कार्यप्रणाली पहले की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी हो गई है. गृहिणियां भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हुनर को पहचान दिलाते हुए घर बैठे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं.

हर गांव तक पहुंच रही 5जी ताकत- मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में जियो के पास कुल 5जी स्पेक्ट्रम क्षमता का 70% से अधिक हिस्सा है, जो दोनों राज्यों के सभी जिलों के 10 हजार से अधिक गांवों तक उपलब्ध है. जियो की स्टैंडअलोन ट्रू 5जी सेवा अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच चुकी है.

बेहतर एंटरटेनमेंट और डिजिटल अनुभव

जिओ फाइबर और जिओ एयरफाइबर कनेक्शन के साथ उपभोक्ताओं को 4च्च में क्रिकेट देखने का शानदार अनुभव, 1000+ टीवी चैनल,लाइव टीवी फीचर्स (जिसमें 350+ एचडी चैनल शामिल हैं), 13+ओटीटी ऐप्स और अनलिमिटेड वाई-फाई जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. ये सेवाएं घर को एक स्मार्ट डिजिटल हब में बदल रही हैं.

पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा केरोसिन

तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 30 मार्च. केंद्र सरकार ने बढ़ते वैश्विक तेल संकट के बीच केरोसिन वितरण को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब राशन दुकानों के साथ-साथ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन मिलेगा.

सरकार ने 60 दिनों के लिए पीडीएस नियमों में ढील दी है, जिससे सप्लाई तेज और सुचारु हो सके. यह फैसला मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से घबराकर खरीदारी न करने की अपील की है.

वैश्विक तेल संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए केरोसिन वितरण के नियमों में बड़ी ढील दी है. अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला केरोसिन केवल राशन दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल

मिडिल ईस्ट तनाव से तेल 116 डॉलर पार

नई दिल्ली, 30 मार्च. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 3.66त्न बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि डब्लूटीआई क्रूड भी 103 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है.

हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव जारी रहा तो तेल 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. इसका असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर महंगाई, कंपनियों के मुनाफे और शेयर बाजार पर पड़ सकता है. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखने लगा है. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों और आयात-निर्भर देशों की चिंता बढ़ गई है. ब्रेंट क्रूड 3.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 116.70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जो पिछले 52 हफ्तों के उच्च स्तर के आसपास है. वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 3 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. तेल की कीमतों में यह तेजी यमन के हूती विद्रोही समूह के इजरायल पर मिसाइल हमलों के बाद आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है.

1 अप्रैल से डिजिटल भुगतान के लिए नए नियम

नई दिल्ली, 30 मार्च.1 अप्रैल, 2026 से, डिजिटल भुगतान के लिए आरबीआई के नए नियमों से भारतीयों के ऑनलाइन लेनदेन करने का तरीका बदल जाएगा।

यदि आप यूपीआई, कार्ड या वॉलेट का उपयोग करते हैं, तो अतिरिक्त सुरक्षा जांच की उम्मीद करें। भारतीय रिज़र्व बैंक दो-कारक प्रमाणीकरण (ओटीपी) को अनिवार्य बना रहा है, जिसका अर्थ है कि अब केवल ओटीपी ही पर्याप्त नहीं होगा। कई उपयोगकर्ता आरबीआई के 1 अप्रैल से लागू होने वाले डिजिटल भुगतान नियमों, यूपीआई भुगतान में होने वाले बदलावों और दैनिक लेनदेन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी खोज रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन लक्ष्य सरल है - डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाना और धोखाधड़ी को कम करना। यहां बताया गया है कि वास्तव में क्या बदलाव हो रहे हैं. डिजिटल भुगतान के लिए नए नियम-अब केवल ओटीपी ही पर्याप्त नहीं होगा. प्रत्येक भुगतान में कम से कम दो सत्यापन विधियों का उपयोग करना अनिवार्य है. इनमें पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स या टोकन शामिल हो सकते हैं. सरल शब्दों में, प्रत्येक लेनदेन अब सुरक्षा की दो परतों से गुजरेगा. आरबीआई के नए नियमों के तहत ओटीपी अब ऑटो का सिर्फ एक हिस्सा रह गया है। प्रमाणीकरण-पिन या फिंगरप्रिंट जैसे दूसरे चरण की आवश्यकता है, इससे अनधिकृत पहुंच की संभावना कम हो जाती है. कुछ व्यावहारिक बदलाव- अतिरिक्त सत्यापन के कारण भुगतान में थोड़ा अधिक समय लग सकता है.विश्वसनीय उपकरणों पर नियमित उपयोगकर्ताओं को सुगम लेनदेन का अनुभव हो सकता है.

समाचार विशेष

ममता के सामने भाजपा कितनी स्ट्रॉन्ग

बंगाल में वोटों का अंकगणित

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिल रहा है. इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' का है.

2021 के विधानसभा चुनावों के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव बंगाल की पार्टियों के लिए सबसे ताज़ा चुनावी परीक्षा रही. ये चुनाव टीएमसी के दबदबे की तस्वीर पेश करते हैं. पांच साल पहले के चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी. बीजेपी पूरे राज्य में अपनी पैठ बना चुकी है. हालांकि इस बार बीजेपी संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को सत्ता से हटाने की एक और कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए यह एक बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है. 2011 में जब से टीएमसी पहली बार सत्ता में आई, तब से हर विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रही है. 2011 में 184 सीटों से बढ़कर 2021 में 215 सीटें हो गईं, जो 294 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए ज़रूरी 148 सीटों के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा हैं. हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को एक झटका लगा था, जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थीं, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थीं. 2024 के चुनावों में सत्ताधारी पार्टी ने वापसी करते हुए 29 लोकसभा सीटें हासिल कर लीं, जबकि बीजेपी को 12 सीटें मिलीं. फिर भी टीएमसी 2014 के लोकसभा चुनावों में बनाए गए अपने रिकॉर्ड 34 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई.

> **बीजेपी के मुकाबले दोगुनी सीटों पर टीएमसी का दबदबा**
>
> विधानसभा क्षेत्र स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से पता चलता है कि टीएमसी अभी भी मज़बूत हालत में है. हालांकि वह 2021 के विधानसभा चुनावों जितना हावी नहीं है. 2024 में टीएमसी ने 192 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जो बीजेपी की 90 क्षेत्रों में बढ़त से दोगुनी से भी ज़्यादा है. कांग्रेस ने 11 क्षेत्रों में और सीपीआई एम ने केवल एक क्षेत्र में बढ़त बनाई. ये आंकड़े टीएमसी को बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ऊपर रखते हैं, भले ही बीजेपी ने अपनी स्थिति मज़बूत की हो.

बृजभूषण और धनंजय सिंह की बढ़ती दोस्ती

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय दो दिग्गज क्षत्रिय नेताओं बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह की बढ़ती नजदीकी चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है.

हाल ही में एक मंच पर साथ आकर इन दोनों नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी यह दोस्ती 2027 के चुनावी रण में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है. इस सियासी जुगलबंदी की शुरुआत गोंडा में आयोजित राष्ट्र कथा के दौरान देखी गई थी, जिसे हाल ही में जौनपुर के होली मिलन कार्यक्रम ने और मजबूती दी. इन दोनों मौकों पर दोनों नेताओं का एक साथ आना यह संदेश दे रहा है कि वे भविष्य के लिए किसी साझा राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं. राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह जोड़ी इसी तरह साथ रही, तो आगामी चुनावों में भाजपा के स्थानीय समीकरणों और नीतियों को कड़ी चुनौती मिल सकती है. इसी बीच, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के भावुक होने से एक और राजनीतिक पहलू सामने आया है.

भाजपा ने गुवाहाटी सेंट्रल से विजय गुप्ता को उतारा

गुवाहाटी. पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी ने गुवाहाटी सेंट्रल सीट से विजय कुमार गुप्ता को उतारा है. बीजेपी ने गुप्ता की उम्मीदवारी के लिए सहयोगी दल असम गढ़ परिषद के रामेंद्र नारायण कलिता का टिकट काटा है. विजय कुमार गुप्ता की उम्मीदवारी के बाद राजधानी गुवाहाटी की इस सीट पर च्स्थानीय बनाम बाहरी की चर्चा जोर पकड़ रही है.

बीजेपी कैंडिडेट लंबे वक्त तक संगठन में रहे हैं. उनके सामने दो महिला कैंडिडेट हैं. जिनसे गुप्ता का मुकाबला होगा. कांग्रेस की सहयोगी पार्टी असम जातीय परिषद ने 27 साल की कुंकी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस सीट से अनुपूर्णा देकराजा को कैंडिडेट बनाया है.

इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,819 है. विधानसभा क्षेत्र में कुल 201 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. बीजेपी, एजेपी और आप के कैंडिडेट तय होने के बाद यहां पर मुकबला अनुभवी बनाम युवा और परिवर्तन का हो गया है. बीजेपी से कैंडिडेट बनने के बाद विधानसभा क्षेत्र में छिड़ी स्थानीय बनाम बाहरी की बहस पर विजय गुप्ता ने अपनी स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार 1925 में यहां आया था. मेरा जन्म तथा पालन-पोषण असम में ही हुआ है. मैंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुए बिताया है, हालांकि इसके बाद भी इस सीट पर असमिया बनाम गैर-असमिया की बहस जारी है.

भाषा पर विवाद गलत- विजय गुप्ता असम में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं. उन्होंने पार्टी में कई पदों पर काम किया है और लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे. 2023 के परिसीमन के बाद गुवाहाटी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया. जिससे मौजूदा विधायक रामेंद्र नारायण कलिता के पास कोई सीट नहीं बची.

बुजुर्ग नेता का युवा कैंडिडेट से मुकाबला

बीजेपी ने जहां बुजुर्ग नेता पर दांव खेला है तो वहीं कांग्रेस की सहयोगी दल से 27 साल की कुंकी चौधरी उनके सामने हैं. विजय गुप्ता ने पूर्व में बीजेपी के प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष और लंबे समय तक कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर काम किया है. वे लंबा अनुभव रखते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके सामने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ीं कुंकी चौधरी हैं. वे एजेपी की उस मुहिम का चेहरा हैं जिसके तहत पार्टी शिक्षित और पेशेवर नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है. ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

विशेष | डीएमके के साथ आई वीसीके, जानें सियासी चाल

तमिलनाडु में साथ, पुडुचेरी में खिलाफ!

चेन्नई. एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने अपने चुनावी गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. डीएमके ने वीसीके के साथ सीटों के बंटवारे का समझौता पक्का कर लिया है.

इस समझौते के तहत डीएमके ने तमिलनाडु में होने वाले आगामी चुनावों के लिए दलितों पर केंद्रित इस पार्टी को विधानसभा की आठ सीटें आवंटित की हैं. कई दौर की बातचीत के बाद पक्का हुआ यह समझौता, वीसीके को छह आरक्षित सीटें और दो सामान्य सीटें देता है. इस समझौते पर डीएमके के मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन की मौजूदगी में औपचारिक रूप से दस्तखत किए गए.

सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वीसीके ने अपनी बढ़ती राजनीतिक अहमियत का हवाला देते हुए सीटों में ज्यादा हिस्सेदारी मांगी थी जिसमें दो अंकों में सीटों का बंटवारा और राज्यसभा की एक सीट शामिल थी. हालांकि डीएमके ने पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी की हिस्सेदारी में थोड़ी बढ़ोतरी करके बीच का रास्ता निकाला, लेकिन उसकी सभी मांगें नहीं मानीं. 2021 के विधानसभा चुनावों में वीसीके ने छह सीटों पर चुनाव लड़ा था और चार सीटें जीती थीं. इस प्रदर्शन ने इस बार बातचीत में उसकी स्थिति को मजबूत किया.

अब भले ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है लेकिन वीसीके ने आज ही दिन में यह ऐलान किया कि वह पुडुचेरी की तीन विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

> **मजबूत गठबंधन बनाने में जुटी डीएमके**
>
> 2026 के चुनावों के लिए सीटों में की गई यह बढ़ोतरी एमके स्टालिन की पार्टी की अपने सहयोगी का समर्थन बनाए रखने की कोशिश को दिखाती है, साथ ही यह बड़े गठबंधन के दायरे में संतुलन भी बनाए रखती है. अब जब यह समझौता हो गया है तो वीसीके ने औपचारिक रूप से डीएमके द्वारा तय की गई शर्तों के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. जिससे सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत को लेकर हफ्तों से बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है. इस घटनाक्रम को सत्ताधारी पार्टी के लिए एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वह चुनावों से पहले एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटी है.